

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 181*

14.03.2023 को उत्तर के लिए नियत

“इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग”

*181. श्री अनुभव मोहंती:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत की सड़कों पर, विशेषकर ओडिशा में, इस्तेमाल में लाए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) इस संख्या का कुल वाहनों की तुलना में राज्य-वार कुल अनुपात कितना है;

(ग) वर्तमान में देश भर में इलेक्ट्रिक कारों के चालकों के लिए राज्य-वार कितनी ई-चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए विनिर्माता और ग्राहक दोनों के लिए बैटरियों की कीमतों पर कोई प्रोत्साहन दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (च) : विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

“इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग” के संबंध में, लोकसभा में दिनांक 14.03.2023 को उत्तर के लिए नियत श्री अनुभव मोहंती के तारांकित प्रश्न संख्या 181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): वाहन-4 पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र के संबंध में उपलब्ध केंद्रीकृत डेटाबेस के मुताबिक, 06.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल वाहनों के अनुपात में इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार (ओडिशा सहित) संख्या **अनुलग्नक-I** में है।

(ग): विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर है।

(घ) और (ङ): जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक सस्ता बनाने के लिए बैटरियों की कीमत पर कोई आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता। किंतु, भारी उद्योग मंत्रालय ने उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम शुरू की है जिसमें उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माताओं को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। पीएलआई एसीसी स्कीम का ब्यौरा <http://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487> पर है।

(च): जी हां। ओडिशा सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में तैयार की और फिलहाल फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए सब्सिडी दी जानी है।

फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत सहायता-प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या (ओडिशा सहित) **अनुलग्नक-III** में है।

साथ ही, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए निम्नांकित उपाय किए हैं:

(i) सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम का बजट परिव्यय 18,100 करोड़ रूपए है।

(ii) ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक से जुड़ी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (जिसे 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय से 5 वर्ष की अवधि के लिए 15 सितंबर, 2021 को

अनुमोदित किया गया है) के अंतर्गत भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(iii) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है और चार्जर्स/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेटें दी जाएंगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

(v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथ-कर न लेने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

अनुलग्नक-1

14.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 181 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

06.03.2023 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रिक और कुल वाहन संख्या का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या	कुल वाहन संख्या	समानुपात
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	182	1,58,315	0.00115
2	आंध्र प्रदेश	51,322	1,59,62,424	0.00322
3	अरुणाचल प्रदेश	24	2,90,622	0.00008
4	असम	94,929	51,78,788	0.01833
5	बिहार	1,28,885	1,12,35,698	0.01147
6	चंडीगढ़	5,533	8,25,027	0.00671
7	छत्तीसगढ़	40,516	72,67,618	0.00557
8	दिल्ली	2,03,263	1,40,12,763	0.01451
9	गोवा	8,710	11,86,956	0.00734
10	गुजरात	99,236	2,22,48,231	0.00446
11	हरियाणा	56,243	1,18,52,730	0.00475
12	हिमाचल प्रदेश	1,877	21,29,378	0.00088
13	जम्मू और कश्मीर	7,080	19,87,453	0.00356
14	झारखंड	28,395	68,66,827	0.00414
15	कर्नाटक	1,83,536	2,93,84,250	0.00625
16	केरल	65,545	1,65,74,564	0.00395
17	लद्दाख	47	41,404	0.00114
18	मध्यप्रदेश	42,957	1,83,07,752	0.00235
19	महाराष्ट्र	2,26,134	3,36,60,442	0.00672
20	मणिपुर	1,052	5,43,568	0.00194
21	मेघालय	83	5,00,953	0.00017
22	मिजोरम	76	3,44,378	0.00022
23	नागालैंड	60	4,05,992	0.00015
24	ओडिशा	45,562	1,04,24,349	0.00437
25	पुदुचेरी	3,376	13,11,922	0.00257
26	पंजाब	25,597	1,29,57,699	0.00198
27	राजस्थान	1,43,273	1,84,43,455	0.00777
28	सिक्किम	21	1,05,211	0.00020
29	तमिलनाडु	1,29,153	3,10,67,518	0.00416
30	त्रिपुरा	12,229	7,00,334	0.01746
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र	303	3,66,873	0.00083
32	उत्तरप्रदेश	4,65,432	4,30,00,681	0.01082
33	उत्तराखंड	42,308	35,96,346	0.01176
34	पश्चिम बंगाल	57,512	1,48,95,998	0.00386
	सकल योग	21,70,451	33,78,36,519	0.00642

अनुलग्नक-II

14.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 181 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

प्रचालनरत राज्यवार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन(पीसीएस)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रचालनरत पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्रप्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	48
5	बिहार	83
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	46
8	दिल्ली	1845
9	गोवा	44
10	गुजरात	195
11	हरियाणा	232
12	हिमाचल प्रदेश	27
13	जम्मू और कश्मीर	24
14	झारखंड	60
15	कर्नाटक	704
16	केरल	192
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्यप्रदेश	174
19	महाराष्ट्र	660
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	19
22	नागालैंड	6
23	ओडिशा	117
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	126
26	राजस्थान	254
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	441
29	तेलंगाना	365
30	त्रिपुरा	18
31	दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
32	उत्तरप्रदेश	406
33	उत्तराखंड	48
34	पश्चिम बंगाल	189
	कुल	6586

अनुलग्नक-III

14.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 181 के भाग(च) के उत्तर में संदर्भित
अनुलग्नक
फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत सहायता-प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या
(02.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल बिक्री
1	जम्मू कश्मीर	3409
2	हिमाचल प्रदेश	1211
3	पंजाब	10380
4	चंडीगढ़	1270
5	उत्तराखंड	9566
6	हरियाणा	17708
7	दिल्ली	58226
8	राजस्थान	63755
9	उत्तरप्रदेश	41134
10	बिहार	19299
11	सिक्किम	9
12	अरुणाचल प्रदेश	3
14	मणिपुर	423
16	त्रिपुरा	2808
17	मेघालय	48
18	असम	3929
19	पश्चिम बंगाल	10760
20	झारखंड	8988
21	ओडिशा	28975
22	छत्तीसगढ़	20709
23	मध्यप्रदेश	31860
24	गुजरात	78133
27	महाराष्ट्र	155405
28	आंध्रप्रदेश	37282
29	कर्नाटक	129717
30	गोवा	6181
31	लक्षद्वीप	7
32	केरल	44871
33	तमिलनाडु	88404
34	पुदुचेरी	1703
35	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8
36	तेलंगाना	38183
37	लद्दाख	20
38	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	140
कुल		9,14,524